



म्यांमार में जमीन के नीचे दबे खजाने पर अमेरिका की नजर, गुप्त बातचीत जारी, इन खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन का है मजबूत दबदबा

नाएथीडा

म्यांमार में अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ गई है, जिस मिलिट्री शासन पर लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के बाद सत्ता संचालने के आरोप हैं, उसके साथ अमेरिका गुप्त बातचीत कर रहा है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपा ऐसा खजाना है, जिस पर चीन की मजबूत पकड़ है। ये खजाना रैयर अर्थ हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों, विंड एनर्जी और आधुनिक तकनीक में होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और म्यांमार के मिलिट्री लीडरशिप के बीच पिछले हफ्ते दोक्यों में एक और दौर की बातचीत हुई,

जो एक महीने के अंदर दोनों पक्षों की दूसरी बैठक थी। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में अमेरिकी विदेश विभाग के खुफिया और रिसर्च डिपार्टमेंट के सहायक सचिव माइकल वेंस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अमेरिका के लिए ये खनिज अहम हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट से लेकर विंड एनर्जी के टर्बाइन तक, कई टेक्नोलोजी में इनकी जरूरत पड़ती है। समस्या यह है कि इन खनिजों को सप्लाई चेन पर चीन का मजबूत दबदबा है, जो सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें साफ करने, प्रोसेस करने और उद्योगों में इस्तेमाल लायक बनाने की

क्षमता भी रखता है। अगर चीन सप्लाई रोकता है, तो इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और दूसरे आधुनिक उद्योगों पर असर पड़ सकता है। दुनिया में भारी रैयर अर्थ की करीब आधी सप्लाई म्यांमार के काचिन राज्य की खदानों से आती है, और वहां से निकले खनिजों का बड़ा हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए चीन भेजा जाता है। अमेरिका इसी व्यवस्था में अपनी जगह बनाना चाहता है ताकि चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सके। हालांकि, अमेरिकी रणनीति के सामने बड़ी मुश्किलें भी हैं। म्यांमार में जिन इलाकों में रैयर अर्थ खदानें हैं, उनमें से कुछ पर वहां की सेना का नियंत्रण नहीं है। काचिन राज्य

में काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जैसे सशस्त्र जातीय संगठनों का प्रभाव है। इसके अलावा, म्यांमार के पास इन खनिजों को उस स्तर तक शुद्ध करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है जिसकी आधुनिक उद्योगों में जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका म्यांमार से खनिज हासिल भी कर ले, तो उसे उनकी प्रोसेसिंग के लिए अलग व्यवस्था बनानी पड़ सकती है। इस पूरी कहानी में भारत का पहलू भी अहम है, भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने बताया था कि महत्वपूर्ण खनिजों की संभावनाएं तलाशने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दिसंबर 2024 और फरवरी 2026 में म्यांमार गया था।

न्यूज़ ब्रीफ

आज बलोचिस्तान जल रहा, नौजवान पहाड़ों पर चढ़ गए हैं: मेंगल



इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आपरेशन का लाइसेंस तो दे दिया गया, लेकिन बलोचिस्तान में कितने आपरेशन किए गए और उनके क्या नतीजे निकले आज बलोचिस्तान जल रहा है और नौजवान पहाड़ों पर चढ़ गए हैं। द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मेंगल ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और उनके साथियों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, इस प्रांत के चुने हुए मुख्यमंत्री और स्पीकर गायब हैं। उनकी सरकार भी छीन ली गई है और शांतिपूर्ण विरोध की इजाजत नहीं है। ऐसा सिस्टम काम नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि वे गुलाम हैं, लेकिन जब तक हम एक देश नहीं बन जाते, हमें गुलाम ही रखा जाएगा। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि स्पीकर एक संवैधानिक पद है और इस पद पर बैठे व्यक्ति को मार्शल ला के समय भी गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन आज स्पीकर देश से गायब हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में लोकतंत्र के दावे किसके आधार पर किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि एक तरफ चुने हुए प्रतिनिधि और मंत्री गैरहाजिर हैं, वहीं दूसरी तरफ फार्म 47 के जरिए चुने गए सदस्य भी गैरहाजिर हैं। छह अक्टूबर 1962 को खुजदार में जन्मे अख्तर बलोचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री मीर अताउल्लाह मेंगल के पुत्र हैं। वह भी 1997 से 1998 तक बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य भी रहे हैं। वह पाकिस्तानी सेना और सरकार की नीतियों की कड़े आलोचनक हैं। वह पाकिस्तान से अलगाव और बलोचिस्तान के हालात को लेकर तीखे राजनीतिक बयान देने के लिए जाने जाते हैं।

यूरोपीय देश गैस आपूर्ति के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गए: नोवाक



मास्को। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि यूरोपीय देशों ने अपने गैस आयात के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश तो की पर वह अमेरिका पर निर्भर हो गए हैं। नोवाक ने रशियन एनर्जी वीक फोरम के दौरान सोलोवोव लाइव ब्रांडकास्टर को दिए साक्षात्कार में कहा, यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति की मात्रा कम हो गई है। उनकी लागत चार गुना बढ़ गई है। अब वह मुख्य रूप से एक ही आपूर्तिकर्ता अमेरिका से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) पर निर्भर हैं। नोवाक ने कहा कि यूरोप में गैस की कीमतें बढ़कर 1,000 डॉलर प्रति 1,000 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई हैं, जबकि 10 साल पहले और कोरोना महामारी से पहले भी ये कीमतें 200 से 250 डॉलर के दायरे में थीं। इसका खामियाजा यूरोपीय उपभोक्ताओं को भुगताना पड़ रहा है। रशियन एनर्जी वीक का आयोजन मास्को में 14 से 16 अक्टूबर के बीच किया गया। रिया नोवोस्ती इस फोरम का सूचना भागीदार रहा।

नेपाल के हिमालयी जिलों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंचा



काठमांडू. नेपाल के हिमालयी जिलों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। तापमान में लगातार गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के प्रवक्ता ने बताया कि 17 हिमालयी जिलों के तापमान संबंधी आंकड़ों के अनुसार, हुन्ता, जुम्ला रोल्पा, डोल्पा, मनांग, मुस्तांग सहित एक दर्जन जिलों के उत्तरी इलाके में सबसे कम न्यूनतम तापमान माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन इलाकों में बीते शनिवार को न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री और शुक्रवार को 3.0 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह संखुआ सभा, रसुवा, बाजुरा, मुगु, कालिकोट जैसी उत्तरी सीमावर्ती इलाकों का तापमान शून्य डिग्री के आसपास पहुंच गया है। जहां-जहां तापमान शून्य के आसपास है उन इलाकों में बर्फबारी होने की जानकारी दी गई है। महाशाखा के अनुसार, रविवार सुबह 8:45 बजे काठमांडू का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को यह 13.8 डिग्री और शुक्रवार को 15.0 डिग्री सेल्सियस था। रविवार को ओखलढुंगा में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस, डडेल्धुरा में 5.9 डिग्री सेल्सियस, ताप्लेजुंग में 3.7 डिग्री सेल्सियस, वीरेन्द्रनगर में 4.3 डिग्री सेल्सियस, दीपायल में 5.5 डिग्री सेल्सियस, धनकुटा में 5.6 डिग्री सेल्सियस, घोराही में 7.0 डिग्री सेल्सियसऔर पोखरा में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अल्बानिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन पुलिस ने दागीं रबर की गोलियां

तिराना

यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप पर बसे अल्बानिया में जेन-जी युवा शिक्षा में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और शिक्षा मंत्रालय में घोटाले को लेकर पिछले पांच दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र हिंसक हो गए। प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और बैंकों में आग लगा दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई और अन्य संयमित हथियारों का भी उपयोग किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया है।

अल्बानिया के प्रमुख पुलिस अधिकारी स्केंडर हिता ने रबर की गोलियां चलाने से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए हैं, उन्हें सीमित दायरे में ही इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ अपने अधिकारियों का गलत प्रयोग करने पर सात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने उचित बल प्रयोग के सिद्धांत का पालन नहीं किया। हिता ने जानकारी दी कि इस प्रदर्शन के दौरान अभी तक 1,067 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और 388 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कई आंदोलनकारी और पुलिसवाले घायल भी हुए हैं। बाल्कन प्रायद्वीप का यह देश कश्चित भ्रष्टाचार और नौकरियों की कमी से जूझ रहा है, और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देश में शिक्षा का स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है।

छात्रों और प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सबसे बड़ा निशाना प्रधानंत्री एडी रामा बने हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने चौथे कार्यकाल की शुरुआत की है। पिछले हफ्ते जब उनसे प्रदर्शनकारियों के दबाव में इस्तीफा देने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इससे साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध का सम्मान करती है, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा। एक फेसबुक लाइव के दौरान अपनी बात रखते हुए रामा ने कहा, इस मुश्किल समय में मेरी जिम्मेदारी और भी स्पष्ट हो जाती है... अपने नागरिकों की रक्षा करना, न्याय सुनिश्चित करना और अल्बानिया को आगे ले जाना। उन्होंने 2030 तक अल्बानिया को यूरोपीय संघ



खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लागू करने पर पीएम ने दी सफाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल और गवर्नर शासन लागू होने के बाद, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में असहयोग के कारण उनकी सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरीफ ने इस स्थिति के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई प्रांतीय सरकार के अधिकार छीनने को एक अनिच्छा से उठाया गया कदम बताया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने उक्त पार्टी के साथ मामले को सुलझाने के लिए लगातार 48 घंटे तक मैराथन बातचीत की थी और एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था जिसके तहत उक्त पार्टी को अपना लाना मार्च वापस लेना था। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन इसके जवाब में हर दूसरे दिन धमकियां और लंबे मार्च निकाले जा रहे थे। अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कार्यकाल के दौरान टी-डीक पर दिए गए धरनों और पिछले साल हुए हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए उन्होंने उक्त पार्टी के रवये को भयानक करार दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदरी ने संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत 11 अक्टूबर 2026 को खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल की घोषणा की थी। इस आदेश के तहत प्रांत की चुनी हुई सरकार को निलंबित कर सीधे गवर्नर रुल लागू कर दिया गया, जिससे सारी प्रशासनिक और राजनीतिक ताकत गवर्नर के हाथ में चली गई है। इसके बाद से उक्त पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमनकारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

का हिस्सा बनाने का लक्ष्य भी दोहराया है, जिसकी प्रक्रिया में अल्बानिया मॉटेनेग्रो के साथ सबसे आगे है। हालांकि, विरोधियों का आरोप है कि रामा सरकार के अधीन अल्बानिया उन गिरोहों का केंद्र बन गया है जो नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से कमाए गए काले धन को सफेद (मनी लांड्रिंग) करना चाहते हैं।

इससे अल्बानिया के यूरोपीय संघ में शामिल होने के प्रयासों में मुश्किलें आ रही हैं। इन आरोपों को तब और बल मिला जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर द्वारा तटीय इलाके में एक रिसॉर्ट बनवाने के लिए जमीन खरीदने का मामला सामने आया।

फ्रांस में मैक्रों के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज

पेरिस (फ्रांस)

फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। लगभग साढ़े पांच लाख लोग सड़कों पर उतरे। अकेले राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग एक लाख बताई गई है। आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्थिति बेकाबू होने पर लाठीचार्ज करना पड़ा। सरकार विरोधी प्रदर्शन राजधानी से बाहर अन्य इलाकों में फैल गया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, गृहमंत्री लॉरेंट नुंजे ने बताया कि पूरे फ्रांस में लगभग 5,50,000 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिनमें से 1,10,000 लोग पेरिस में थे। आयोजकों का अनुमान है कि यह संख्या और भी अधिक थी। इस सप्ताहांत रेंनेस, ल्योन और मांसिले में भी प्रदर्शन हुए। ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें लोग ऐतिहासिक मूर्तियों पर चढ़े हुए थे और इमारतों में



आग लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि शाम होते-होते लिले और मांसिले में प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों के अंदर घुस गए।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व में लोकतंत्र असुरक्षित है। वह अरबपति हैं और मीडिया को नियंत्रित करते हैं। हम बदलाव को बदलने के लिए लड़ रहे हैं। दक्षिणी फ्रांस के मांसिले में प्रदर्शन शुरू होने से पहले हुई झड़पों के दौरान पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि पेरिस में रात होते ही युवाओं के कुछ समूहों ने लूटपाट की और आग लगा दी। इसके जवाब में

पुलिस ने तंग गलियों में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

मैक्रों ने अराजकता फैलाने वालों की निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, पुलिस थातों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं और टाउन हॉल में लूटपाट की है उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। पेरिस पुलिस ने कहा, हम दंगाइयों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर हमला करने वालों के सामने पीछे नहीं हटेंगे। बताया गया है कि अब तक कम से कम 195 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

मस्क के सैटेलाइट सिस्टम पर प्रतिबंध से यूक्रेन नहीं कर पा रहा ड्रोन का इस्तेमाल: जेलेंस्की



से हो रहा है। जब हम व्हाइट हाउस से पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि यह एलन मस्क की तरफ से है।

मस्क ने एक्स पोस्ट में कहा कि स्टारशील्ड सिस्टम में रुकावट डालने में अमेरिकी सरकार शामिल थी। उन्होंने लिखा, स्टारशील्ड सिस्टम अमेरिकी सरकार के स्वामित्व में है और उसी के

नियंत्रण में है। इसकी स्पीड या इस्तेमाल पर कोई भी पाबंदी अमेरिकी सेना और अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति तय करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के इस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने में व्हाइट हाउस का कोई हाथ नहीं है।

यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंध

लगने से पहले स्टारलिनक और स्टारशील्ड नेटवर्क उन ड्रोन पर भी काम करते थे जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे। अब इसे 161 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दिया गया है। जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि देश की सेना ने यूरोपीय संघ के देशों में कारों के जरिए इस सिस्टम का परीक्षण किया। जब कारें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं, तब भी सैटेलाइट सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही कारें यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुईं, 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। जेलेंस्की ने कहा, निष्कर्ष यह है कि ये प्रतिबंध यूक्रेन के अंदर तो लागू हैं, लेकिन यूरोपीय संघ के देशों में नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो, यह एक सुनियोजित कदम है। जेलेंस्की ने स्पेसएक्स के इस दावे पर भी संदेह जताया कि स्पीड लिमिट तकनीकी समस्याओं की वजह से लगी है। उधर, अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रूबियो ने भारत यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा उन्हें

यकीन नहीं है कि जेलेंस्की को पता भी है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। रूबियो ने कहा कि अमेरिकी सरकार में किसी ने भी स्टारलिनक की स्पीड कम करने का आदेश नहीं दिया था। उल्लेखनीय है कि यूक्रेनी सेना अपने तोही और इंटरसेप्टर ड्रोन को नियंत्रित करने और चलाने के लिए स्पेसएक्स के स्टारलिनक सैटेलाइट कन्सिुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। यूक्रेन दो सैटेलाइट सिस्टम पर निर्भर है। एक है स्पेसएक्स का स्टारलिनक। इसका इस्तेमाल संचार, थल सेना, लाजिस्टिक्स और रक्षात्मक ड्रोन (जो दुश्मन के ड्रोन को मार गिराते हैं) के लिए किया जाता है। दूसरा है स्टारशील्ड, जिसे अमेरिकी सरकार नियंत्रित करती है और इसका इस्तेमाल आक्रामक सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जेलेंस्की ने बताया कि शुक्रवार को यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रूसम उमेरोव ने ट्रंप के सलाहकार और दूत जेरेड कुशनर से बात की, जिसमें स्टारलिनक के मुद्दे पर चर्चा हुई।